रांची, झारखंड में उच्च शिक्षा के सामने आने वाली समस्याओं का अध्यन

Kavita[1], Dr. Omkarnath Mishra[2]

Department of Education

[1,2]OPJS University, Churu (Rajasthan) – India

सार

वर्तमान समय में भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था का सही रूप से मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की कमी को आर्थिक मजबूतियों के मत्थे जड़ दिया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए भारत में संसाधनों की उतनी कमी नहीं है जितनी की अच्छे प्रबन्धन की है। अनुभव बताता है कि महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के पास संसाधन होने पर भी अपेक्षित परिमाम नहीं प्राप्त हुये हैं। सुधार हेतु अच्छे प्रबन्धन पर जोर देना आवश्यक है।आज शिक्षा में गुणवत्ता दूर की कौड़ी होती जा रही है। तमाम महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों पर गौर करें तो उनमें नवीनता का सर्वथा अभाव पाते हैं। अधिकतर संस्थान संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी प्राध्यापकों का घोर अभाव है।अतः यह शोध झारखण्ड में उच्च शिक्षा की स्तिथि का अवलोकन करता है

प्रस्तावना

शिक्षा में गुणवत्ता का निर्धारण सुप्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता अध्यापक छात्र का उचित अनुपात, महाविद्यालय में उपलब्ध आधुनिक शैक्षणिक उपकरण तथा आवश्यक कक्षा कक्ष सुविधाओं से किया जाता है।

उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के पीछे निश्चित रूप से, पिछले दशकों में सरकारों की नीतियों में आये बदलाव, सामाजिक जागरूकता और नौकरी में विश्वविद्यालय की डिग्री के बढ़े महत्व की खास भूमिका रही है। स्कूली शिक्षा के दुनिया भर में विस्तार का एक असर ये हुआ है कि प्राथमिक शिक्षित व्यक्तियों की नौकरी में मांग घट गई है। सामान्य नौकरी में भी या तो कौशल आधारित डिग्री या फिर विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री की जरूरत बताई जाने लगी है। दुनिया में बदलते परिदृश्य को देखते हुए, कई देशों ने अपनी उच्च शिक्षा की नीतियों में बदलाव किया है। उच्च शिक्षा की मांग और कॉलेज ध्विश्वविद्यालय की उपलब्धता के बीच संतुलन को बनाये रखने के लिए, कुछ वर्षों तक विश्वविद्यालयों ने अपने स्तर पर प्रयास किया। बजट नहीं बढ़ने, शिक्षकों की भर्ती नहीं होने, लैब–पुस्तकालय नहीं बनने और छात्रों की बढ़ती संख्या का परिणाम ये हुआ कि राज्यों और छोटी जगहों के कॉलेज और विश्वविद्यालय, अपनी गुणवत्ता को नहीं बनाए रख सके। डिग्री प्राप्त करने का मतलब ये नहीं रह गया कि अधिकतर छात्रों को उस विषय का बुनियादी ज्ञान भी है। हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा में नकल की संस्कृति और फर्जी डिग्री के कारोबार को भी बढ़त मिली है।

भारत सहित अन्य एशिया के देशों ने, युवाओं की उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग और शिक्षा संस्थानों की कमी को मिले–जुले तरीके से पूरा करने का प्रयास किया। भारत में जहाँ कुछ नए केंद्रीय और प्रादेशिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, वहीं निजी विश्वविद्यालयों का रास्ता आसान किया गया। सरकारी विश्वविद्यालयों को भी फीस बढ़ाने और स्ववित्तपोषित कोर्स चलाने की अनुमति दी गई। देश के कई नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अभी भी शिक्षकों की सम्पूर्ण नियुक्ति नहीं हुई है और पुराने शासकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में भी प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। भवन, बेंच–डेस्क, लैब आदि के लिए बजट की कमी, विश्वविद्यालयोंध् महाविद्यालयों के सामने एक आम चुनौती है।

दूसरी तरफ, उच्च शिक्षा में निजीकरण का असर ये हुआ कि दो दशक के भीतर, देश भर में निजी कॉलेजोंध् विश्वविद्यालयों की संख्या में जबर्दस्त विस्तार हुआ है। गांव–देहात में निजी महाविद्यालय तो चल रहे हैं लेकिन उनको दक्ष शिक्षक कहाँ से मिल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है ? हम जो बहुमत को पढ़ा रहे हैं, क्या वह 21वीं शताब्दी में जरूरी कौशल हासिल करने में मददगार है या सिर्फ डिग्री धारी जमात तैयार हो रही है। ग्रामीण इलाकों में खुले इन महाविद्यालयों ने निश्चित रूप से

युवा पीढ़ी, विशेष रूप से लड़कियों के अरमानों को पंख दिया है, लेकिन शिक्षा अगर प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो हौसलों की उड़ान जल्दी ही जमीन पर आ जाएगी।

भारत में अगर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया तो दुनिया के अनेक देश जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, स्वीडन आदि आर्थिक रूप से समर्थ भारतीय छात्रों को आकर्षित करने में सफल रहेंगे। प्रत्येक वर्ष शिक्षा के लिए, देश से बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज कल, ऑनलाइन कोर्स का रास्ता भी लोकप्रिय हो रहा है और पत्राचार पाठ्यक्रम का भी मॉडल अपनाया जा रहा है। वहीं वियतनाम जैसे देश ने सरकारी विश्वविद्यालयों को खुद संसाधन जुटाने का जिम्मा दे दिया है। जापान, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया जैसे देशों में निजी संस्थान बहुतायत में खुले हैं। दुनिया भर में, अब सतत प्रशिक्षण–अध्ययन की आवश्यकता से नौकरी–पेशा लोगों में अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोर्स की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत में युवाओं को ऑनलाइन कोर्स में जाना, एक विकल्प होना चाहिए, न कि दबाव में चुना गया रास्ता। जीवन के जटिल अनुभव और सामाजिक जिम्मेदारी के एहसास के लिए विश्वविद्यालयों के कैंपस की अपनी भूमिका होती है और देश के युवाओं को नियमित संस्थानों में पढ़ने का यह अवसर मिलना चाहिए।

अपने देश में, आने वाले दिनों में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना रहेगा या फिर उच्च शिक्षा आयोग बनेगा और इससे क्या बदलाव होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन शिक्षा में जो असमान अवसर व्याप्त हैं, वह कौन दूर करेगा ? ऐसा कैसे होता है कि अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर ये देखा जाता है कि एक मध्यमवर्गी, उच्च वर्गी परिवार से संबन्धित छात्र ध्छात्रा, एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और फिर अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पा जाते हैं। अगर सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं भी मिला तो, किसी निजी विश्वविद्यालय में 20–25 लाख रुपये की फीस देकर कानून–मेडिकल जैसी डिग्री ले लेते हैं। देश के बाहर जाकर, डिग्री लेने का विकल्प तो उनके सामने खुला ही रहता है। क्या एक सामान्य किसान परिवार के छात्र ध्छात्रा को यह अवसर मिलता है ? हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के सवाल में ये बहस शामिल होनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक–आर्थिक असमानता को काम करने वाली हो न कि उसको और बढ़ाने या मजबूत करने वाली हो।

हमारी उच्च शिक्षा असंगत नीतियों की शिकार है। संसार भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत के एक भी संस्थान के शामिल न होने से हमारे राजनेता चिन्तित होते हैं परन्तु इसका तोड़ यह निकाला जाता है कि भारत भर के संस्थानों की ही अपने तईं रैंकिंग कराकर खुश हो लिया जाए। अक्टूबर 2017 में टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) ने दुनिया भर के लॉ यूनिवर्सिटी की जो शीर्ष सूची जारी की है, उसमें शामिल दस विधि विश्वविद्यालयों में से पांच अमेरिका के तथा तीन ब्रिटेन के हैं जबकि भारत का एक भी विश्वविद्यालय शीर्ष सौ में भी शामिल नहीं है। शीर्ष दस विधि विश्वविद्यालयों में प्रथम से चतुर्थ स्थान पर क्रमशः अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी हैं। पांचवें और छठे स्थान पर क्रमशः ब्रिटेन के कैम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी का स्थान सातवां तथा लन्दन यूनिवर्सिटी का स्थान आठवां है। पुनः नौवें स्थान पर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दसवें स्थान पर कनाडा के टोरण्टो यूनिवर्सिटी का वर्चस्व है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है

माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता शिक्षा को कुछ मुख्य आयामों में परिभाषित किया जा सकता है। जिनका सामना प्राय सभी शिक्षार्थी करते है।

- छात्राध्यापको (महाविद्यालय में आने वाले) की मनोदशा
- महाविद्यालय का वातावरण
- माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का पाठ्यक्रम
- माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया
- माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की निष्कर्ष

माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से जुडे इन आयामों को ध्यन में रखकर इस शोध अध्ययन में कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की जायेगी।बालक एवं किशोर छात्र जो शारीरिक, मनौवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ तथा अधिगम एवं विभिन्न शैक्षणिक परिस्थितियों में भाग लेने हेतु तत्पर होते है। इनकी शिक्षा में परिवार व समुदाय का सहयोग शामिल होता है। ऐसे छात्र गुणवत्ता शिक्षा से लाभान्वित होते है एवं संस्‍ था की गुणवत्ता भी बढ़ाते है। परन्तु माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में आने वाले शिक्षार्थियों में अधिकांशतः महिला शिक्षार्थी होती है।

भारतीय परिवेश में महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी निश्चित ही देश को विकास की ओर ले जायेगी, परन्तु जहाँ महिलायें घर से बाहर निकलकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी वे अपना मुँह नही मोड़ सकती, अतः महाविद्यालय में आने वाली महिला शिक्षार्थियों की मनोदशा महाविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावित करती है।''महाविद्यालय की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि महाविद्यालय उनकी मनोदशा को सकारात्मक दिशा प्रदान करने की क्षमता रखता है।''

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रक्रियाऐं –

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रक्रियाओं में सुप्रशिक्षित अध्यापक, जो व्यवसायिक अधिगम तथा विकास से लगातार जुडे रहते हो, छात्रों के लिए सुविधायुक्त कक्षाकक्ष तथा महाविद्यालय, कौशल आधारित एवं छात्र केन्द्रित सहायक अध्ययन तरीके, निर्विध्न अधिगम हेतु कौशलयुक्त मूल्यांकन तथा उपयोगी तकनीकें, आदि को शामिल किया जाता है।गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत शिक्षा तंत्र एवं समुदाय को भी, शिक्षकों के जीवन तथा कार्य हेतु उत्तम परिस्थितियाँ उपलब्ध करवानी चाहिए। महाविद्यालय के प्रबंधक को भी प्रशासनिक अवलम्ब तथा नेतृत्व प्रदान करना चाहिए।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निष्कर्ष

माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ऐसे भावी शिक्षकों को तैयार करता है जो, पठन पाठन, लेखन, गणितीय ज्ञान, विज्ञान, उपलब्ध तकनीकों एवं कौशलों का ज्ञान रखते है। यहीं भावी शिक्षक

मानव विकास तथा राष्टीय विकास को बढ़ते है तथा जीवनभर समुदाय के लिए सकारात्मक सहयोग तथा अधिगम प्रदान करते है।

रांचीझारखण्ड में विश्वविद्यालयों में छात्रों की सीखा की स्तिथि

झारखंड में साक्षरता दर 1991 के 41.39 प्रतिशत की तुलना में 54.13 प्रतिशत हो गई है। यहाँ 21,386 विद्यालय और पाँच विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा यहाँ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जाना– माना व्यापार एवं प्रबंधन संस्थान, जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टिट्यूट और केंद्रीय खनन शोध संस्थान जैसे शैक्षणिक व शोध संस्थान स्थित हैं।जमशेदपुर स्थित इंडो– डैनिश टूल रूम (आई. डी. टी. आर.), रांची स्थित डिजाइन डेवलेपमेंट ऐंड ट्रेनिंग सेंटर और मेन टूल रूम औद्योगिक क्रियाकलापों को कलपुर्जो व प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।जनजातिय प्रदेश होने के बावजूद यहां कई नामी सरकारी एवं निजी कॉलेज हैं जो कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी, मेडिसिन, कानून और मैनेजमेंट में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिये विख्यात हैं ।

शिक्षण संस्थान

- राँची विश्ववविद्यालय, राँची
- सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका
- विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची
- बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, राँची

अन्य संस्थान

- राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर
- राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान, धनबाद
- भारतीय लाह शोध संस्थान, राँची
- राष्ट्रीय मनोचिकत्सा संस्थान, राँची
- जेवियर प्रबंधन संस्थान

उच्च शिक्षा में झारखंड निचले पायदान में एक–दो राज्यों से ही ऊपर है। यहां के कालेजों का ग्रास इनरालमेंट रेशियो (जीईआर) भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। मुख्य सचिव राजीव गौबा ने इस पर चिंता प्रकट करते हुए सभी विश्वविद्यालयों को इसमें अपेक्षित सुधार लाने का टास्क सौंपा है।उच्च शिक्षा का अर्थ है सामान्य रूप से सबको दी जानेवाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष, विशद तथा सूक्ष्म शिक्षा। यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है,जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालयों, लिबरल आर्ट कॉलेजों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है जो प्रायः ऐच्छिक होता है। इसके अन्तर्गत् स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न राज्यों में उच्च शिक्षा से संबंधित अनेक समस्याएँ उजागर हो रही हैं। इसमें झारखंड राज्य भी शामिल है।

शिक्षकों की कमी बड़ी समस्या

झारखंड में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण चुनौती यह भी है कि यहाँ स्थापित अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना जमीन विवादों से जुड़ी रही है। इससे शुरूआती वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए वह धरातल नहीं बना पाया, जिसपर खड़े होकर आनेवाली पीढ़ियाँ अपने भविष्य के सुनहरे सपने गढ़ सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति इतनी कम हुई है कि दूसरे विषयों के शिक्षक किसी अन्य विषय की भी कक्षायें लेते अथवा कॉपियाँ काटते पाये जा सकते हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों का भविष्य अंधकारमय ही नजर आता है। अर्थात् झारखंड में गुणवत्तपूर्ण उच्च शिक्षा की काफी कमी देखी जा सकती है।

गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा देना चुनौती

रांचीः झारखंड में उच्च शिक्षा की नामांकन दर (ग्रास एनरोलमेंट रेशियो या जीइआर) सिर्फ 8.1 फीसदी है. यानी राज्य में सौ में से सिर्फ 8.1 फीसदी युवा ही उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज या विवि तक पहुंच पाते हैं.यह जीइआर के राष्ट्रीय औसत 19.4 फीसदी से भी कम है. सरकार उच्च शिक्षा की इस दुर्दशा पर चिंतित तो लगती है, पर इसके लिए त्वरित उपाय नहीं किये जा रहे. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने यह लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2022 तक नामांकन दर कम–से–कम 32 फीसदी तक बढ़ायी जाये. इसके लिए कॉलेजों की संख्या बढ़ाने से लेकर मौजूदा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं व कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है. पर अमल में भारी विलंब हो रहा है. लंबित योजनाओं में 11 जिलों में महिला मॉडल कॉलेज बनाना तथा विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों की प्रयोगशाला व पुस्तकालय का विकास कार्य सहित अन्य शामिल हैं. राज्य के 11 पिछड़े जिलों में महिला साक्षरता की दर बढ़ाने के लिए मॉडल कॉलेज बनने हैं, महिला मॉडल कॉलेज की योजना तो करीब चार साल पुरानी है, जिस पर अब तक कार्य शुरू नहीं हो सका है. उसी तरह कॉलेजों के कैंपस डेवलपमेंट, लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण, लैब अपग्रेडेशन जैसे कई काम अपवाद छोड़ किसी कॉलेज में पूरा तो दूर तीन वर्ष बाद अभी शुरू भी नहीं हुआ है. शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी समस्या है. अब राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति राष्ट्रीय

उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत सुधारी जायेगी. केंद्र सरकार ने रूसा के तहत झारखंड के लिए 206 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया है.

उच्च शिक्षा में पड़ोसियों से काफी पीछे झारखंड

केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने उच्च शिक्षा और इसे बढ़ावा देनेवाले संस्थानों की रिपोर्ट जारी की है। इसमें झारखंड की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। राज्य में केंद्रीय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय 14 हैं। वहीं, पड़ोसी राज्य बिहार में 22, ओडिशा में 21, पश्चिम बंगाल में 34 और छत्तीसगढ़ में 22 विवि हैं।विभाग की रिपोर्ट मुताबिक देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 774 है। देश में सबसे ज्यादा 67 विश्वविद्यालय उत्तरप्रदेश में हैं। वहीं, गोवा में सिर्फ 2 हैं।देश में उच्च शिक्षा दर 24.5 प्रतिशत : देश में उच्च शिक्षा दर 24.5 प्रतिशत है। इसमें पुरुषों के बीच उच्च शिक्षा दर 25.4 प्रतिशत और महिलाओं के बीच 23.6 प्रतिशत। एससी विद्यार्थियों के बीच उच्च शिक्षा दर 14.2 और एसटी विद्यार्थियों का 19.9 प्रतिशत उच्च शिक्षा दर है।

नैक से मान्यता लेने में फिसड्डी रह गए झारखंड के कॉलेज

रांची,झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेज विभिन्न मापदंडों में अन्य राज्यों से काफी पीछे हैं। नैक से एक्रीडिएशन (मान्यता) लेने में भी ये फिसड्डी हैं। यहां के शैक्षणिक संस्थानों में सुविधाओं और शिक्षकों की उपलब्धता तथा वहां दी जा रही गुणवत्तापूर्ण स्थिति का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थिति यह है कि वर्तमान में राज्य के मात्र एक विश्वविद्यालय तथा सोलह कॉलेजों को ही यह अर्हता प्राप्त है।उल्लेखनीय है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जारी 'इंडिया रैंकिंग–2016 ' में झारखंड का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। इसमें देश के टॉप सौ विश्वविद्यालयों, इतने ही इंजीनियङ्क्षरग कॉलेजों तथा 50–50 मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों की रैंकिंग की गई है। इस रैंकिंग में राज्य सरकार का अपना एक भी उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थान नहीं बना पाया। अलबत्ता आइआइएम–रांची, बीआइटी मेसरा, एक्सएलआरआइ तथा एनआइटी–जमशेदपुर अपनी–अपनी फैकल्टी में स्थान पाने में सफल रहे।

उपसंहार

झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहाँ आदिवासी समाज सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है। वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने के बाद झारखंड कई क्षेत्र में विकास कर रहा है लेकिन शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति निराशाजनक हैं।इंटर या आईएससी के बाद यहाँ के मेधावी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर के राज्यों में चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि उच्चतर शिक्षा से संबंधित सरकारी शिक्षण संस्थानों की काफी कमी के कारण निजी शिक्षण संस्थानों में फीस के नाम पर एक मोटी रकम वसूली जाती है, जिसपर अंकुश लगाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास न के बराबर हो रहे हैं। हरियाणा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में झारखंड के ज्यादातर छात्र उच्च शिक्षा की कल्पना में पलायन करते हैं, क्योंकि इन राज्यों की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पूंजी निवेश करती हैं। इस वजह से नर्सिंग, बीएड, बीएचएमएस, डेंटल साइंस, माइक्रोबाइलोजी जैसे उच्चतर तकनीकी शिक्षा झारखंड की तुलना में वहां सस्ती हैं।ऐसी स्थिति झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था को दो तरीके से हानि पहुंचाती है–पहला, उच्च शिक्षा के नाम पर झारखंड की पूँजी दूसरे राज्यों में निवेश होकर वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर रही है तो दूसरा, हमारे राज्य की बौद्धिक संपदा एक बार पलायनवाद का शिकार होने के बाद दुबारा यहाँ वापस आने का अवसर नहीं ढूँढ़ता, जिस कारण हम अपने ही प्रखर बौद्धिक संपदा को भी सरलता से दूसरे को सौंपने के लिए बाध्य हो रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. किशन, एम. रामनाथ 2007: 'ग्लोबल टैंडस इन टीचर एजूकेशन' ए.पी. एच. प्रकाशन, न्यू देहली।
2. करलिंगर, एफ.एन. 2007: 'फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च' सुजीत प्रकाशन, न्यू देहली।
3. रूहेला, एस.पी. 2007: 'टीचर इन दि एमर्जिंग इण्डियन सोस ।यटी' इण्टरनेशनल प्रकाशन हाउस, कॉलेज रोड़, मेरठ।
4. सिंह मया शंकर 2007: 'टीचर एजूकेशन इन डिलीमा; अध्ययन प्रकाशन, न्यू देहली।
5. शर्मा, एस.आर. 2007: 'प्रॉब्लम्स ऑफ एजूकेशनल रिसर्च' अमोल प्रकाशन, न्यू देहली।
6. सांखला, डी.पी. 2007 : 'रिसर्च मैथडोलॉजी इन एजूकेशन' अध्ययन प्रकाशन, न्यू देहली।
7. सिंह, वाई.के. 2007: 'रिसर्च मैथडोलॉजी' ए.पी.एच. प्रकाशन, न्यू देहली।
8. त्रिवेदी, आर.एन. एण्ड शुक्ला डी.ए. 2007: 'रिसर्च मैथडोलॉजी' कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
9. अग्रवाल, जे.सी. 2008, टीचर एजूकेशन : 'थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस' दोआब हाउस, देहली।
10. बेगम, जहीथा ए. तथा भार्गव महेश 2008 : 'इन्नोवेशन्स इन मॉडल एजूकेशनल रिसर्च' राखी प्रकाशन, आगरा।